EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

14 - 20 JUNE 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques : Sanjay Lohiya is currently serving as Secretary of which department?
प्रश्न: संजय लोहिया वर्तमान में किस विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं?

A) Department of Economic Affairs (DEA) / आर्थिक कार्य विभाग (DEA)

B) Department of Revenue / राजस्व विभाग

C) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग (DFS)

D) Department of Expenditure / व्यय विभाग

E) Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) / निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has nominated Sanjay Lohiya as a director on the Central Board of the Reserve Bank of India (RBI).

• भारत सरकार ने संजय लोहिया को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है।

• He has also been nominated as a director on the Central Board of the State Bank of India (SBI).

• उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के केंद्रीय बोर्ड में भी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

• Sanjay Lohiya is currently serving as Secretary, Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance.

• संजय लोहिया वर्तमान में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव हैं।

• The appointment is expected to strengthen coordination between the Government, RBI and the banking sector.

• यह नियुक्ति सरकार, RBI और बैंकिंग क्षेत्र के बीच समन्वय को और मजबूत करेगी।

• The Department of Financial Services is responsible for matters related to banks, insurance companies and financial institutions.

• वित्तीय सेवा विभाग बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार है।

• RBI is India's central bank and is responsible for monetary policy and financial stability.
• RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
• Established – 1 April 1935
• स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Governor – Sanjay Malhotra
• गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Nationalized – 1 January 1949
• राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
• Established – 1 July 1955
• स्थापना – 1 जुलाई 1955
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Chairman – C. S. Setty
• अध्यक्ष – सी. एस. शेट्टी

Ques: According to recent banking sector data, which category accounted for the largest share of fraud amount in FY26?
प्रश्न: हालिया बैंकिंग क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में धोखाधड़ी (Fraud) की कुल राशि में सबसे बड़ा योगदान किस श्रेणी का रहा?

A) Deposits Category / जमा श्रेणी

B) Credit Cards Category / क्रेडिट कार्ड श्रेणी

C) Digital Payments Category / डिजिटल भुगतान श्रेणी

D) Advances (Loan) Category / अग्रिम (ऋण) श्रेणी

E) Foreign Exchange Category / विदेशी मुद्रा श्रेणी

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's banking sector reported frauds worth ₹48,021 crore in FY26.
• भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹48,021 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की गई।
• This represents a 46% increase over ₹32,694 crore reported in FY25.
• यह वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज ₹32,694 करोड़ की तुलना में 46% अधिक है।
• FY26 recorded the highest fraud amount in the last three years.
• FY26 में पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक धोखाधड़ी राशि दर्ज की गई।
• Despite the increase in fraud value, the number of fraud cases declined from 23,722 in FY25 to 10,114 in FY26.
• धोखाधड़ी की राशि बढ़ने के बावजूद मामलों की संख्या FY25 के 23,722 से घटकर FY26 में 10,114 रह गई।
• This indicates a trend of fewer but higher-value frauds.
• इससे संकेत मिलता है कि धोखाधड़ी के मामले कम हुए हैं, लेकिन उनकी राशि अधिक रही है।
• Public Sector Banks (PSBs) accounted for nearly 74% of the total fraud amount.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने कुल धोखाधड़ी राशि का लगभग 74% हिस्सा दर्ज किया।
• PSBs reported frauds worth ₹35,709 crore across 5,418 cases during FY26.
• PSBs ने FY26 में 5,418 मामलों में ₹35,709 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की।
• Private Sector Banks reported frauds worth ₹11,399 crore involving 3,956 cases.
• निजी क्षेत्र के बैंकों ने 3,956 मामलों में ₹11,399 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की।
• The Advances (Loan) Category remained the largest source of banking fraud, accounting for ₹40,774 crore.

• अग्रिम (ऋण) श्रेणी बैंकिंग धोखाधड़ी का सबसे बड़ा स्रोत बनी रही, जिसमें ₹40,774 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की गई।
• Loan-related frauds constituted 84.9% of the total fraud amount in FY26.
• ऋण संबंधी धोखाधड़ी FY26 की कुल धोखाधड़ी राशि का 84.9% हिस्सा थी।
• The number of loan-related fraud cases increased from 7,924 in FY25 to 8,640 in FY26.
• ऋण संबंधी धोखाधड़ी के मामले FY25 के 7,924 से बढ़कर FY26 में 8,640 हो गए।

Ques: According to the latest Global Economic Prospects Report of the World Bank, what GDP growth rate is projected for India in Financial Year 2026-27?
प्रश्न: विश्व बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है?

A) 5.8%
B) 6.2%
C) 6.6%
D) 7.0%
E) 7.2%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the latest Global Economic Prospects Report released by the World Bank, India is expected to remain the world's fastest-growing major economy.
• विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
• India's GDP growth rate is projected at 6.6% for Financial Year 2026-27.
• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है।
• The report projects a further rebound in the Indian economy in the following year.

• रिपोर्ट के अनुसार, अगले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक सुधार होने की संभावना है।
• India's economic growth is expected to reach 7.2% in Financial Year 2027-28.
• वित्त वर्ष 2027-28 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% तक पहुंचने का अनुमान है।
• The report highlights India's strong domestic demand, investment activity, and economic resilience as key growth drivers.
• रिपोर्ट में मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों और आर्थिक लचीलेपन को भारत की वृद्धि के प्रमुख कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has placed which co-operative bank under regulatory Directions for a period of six months?
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस सहकारी बैंक को छह महीने की अवधि के लिए नियामकीय निर्देशों (Regulatory Directions) के तहत रखा है?

A) Saraswat Co-operative Bank / सरस्वत सहकारी बैंक

B) Cosmos Co-operative Bank / कॉसमॉस सहकारी बैंक

C) Janata Sahakari Bank / जनता सहकारी बैंक

D) Shamrao Vithal Co-operative Bank / शामराव विठ्ठल सहकारी बैंक

E) Mogaveera Co-operative Bank Ltd. / मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has placed Mogaveera Co-operative Bank Ltd., Mumbai, under regulatory Directions for a period of six months.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित Mogaveera Co-operative Bank Ltd. को छह महीने की अवधि के लिए नियामकीय निर्देशों (Regulatory Directions) के तहत रखा है।
• RBI clarified that these Directions do not mean cancellation of the bank's licence.

• RBI ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का अर्थ बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है।
• Under the Directions, depositors are allowed to withdraw up to ₹1 lakh from their accounts.
• इन निर्देशों के तहत जमाकर्ताओं को अपने खातों से अधिकतम ₹1 लाख तक निकालने की अनुमति दी गई है।
• The restrictions have been imposed to safeguard the interests of depositors and ensure financial stability.
• ये प्रतिबंध जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं।
• Eligible depositors are protected under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) scheme.
• पात्र जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) योजना के तहत सुरक्षा प्राप्त है।
• Depositors can receive insurance claims up to ₹5 lakh under DICGC coverage.
• DICGC के तहत जमाकर्ताओं को अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा दावा प्राप्त हो सकता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India (RBI) Established – 1 April 1935
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• RBI Headquarters – Mumbai
• RBI मुख्यालय – मुंबई
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• DICGC Established – 15 July 1978
• DICGC की स्थापना – 15 जुलाई 1978
• DICGC Headquarters – Mumbai
• DICGC मुख्यालय – मुंबई
• Deposit Insurance Limit – ₹5 Lakh per depositor per bank
• जमा बीमा सीमा – प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक ₹5 लाख
• DICGC Parent Organization – Reserve Bank of India
• DICGC की मूल संस्था – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

EXAM Genius

Ques: What was India's retail inflation (CPI) rate in May 2026, according to the National Statistical Office (NSO)?
प्रश्न: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) दर कितनी रही?

A) 3.48%
B) 3.75%
C) 3.93%
D) 4.25%
E) 4.50%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), increased to 3.93% in May 2026.
• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2026 में 3.93% दर्ज की गई।
• Retail inflation was 3.48% in April 2026.
• अप्रैल 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.48% थी।
• The May 2026 figure represents the highest retail inflation level in the last 16 months.
• मई 2026 की दर पिछले 16 महीनों में सबसे अधिक खुदरा मुद्रास्फीति स्तर है।
• Despite the increase, inflation remains slightly below the Reserve Bank of India's medium-term target of 4%.
• वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% के मध्यम अवधि लक्ष्य से थोड़ी कम बनी हुई है।
• The inflation data was released by the National Statistical Office (NSO).
• यह मुद्रास्फीति आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए गए।
• NSO functions under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
• NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।

New CPI Series (Base Year 2024 = 100) | नई CPI श्रृंखला (आधार वर्ष 2024 = 100)

• The new CPI series uses 2024 as the base year (2024 = 100).
• नई CPI श्रृंखला में 2024 को आधार वर्ष (2024 = 100) बनाया गया है।
• The total number of weighted items at the all-India level has increased from 299 to 358.
• अखिल भारतीय स्तर पर भारित वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है।
• Goods items increased from 259 to 308.
• वस्तु (Goods) श्रेणी की मदें 259 से बढ़कर 308 हो गई हैं।
• Services items increased from 40 to 50.
• सेवा (Services) श्रेणी की मदें 40 से बढ़कर 50 हो गई हैं।
• The revised basket aims to better reflect current consumption patterns of Indian households.
• संशोधित उपभोग टोकरी भारतीय परिवारों की वर्तमान उपभोग प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए तैयार की गई है।

Ques: What is the tenure of the 'bob Golden Goal Deposit Scheme' launched by Bank of Baroda?
प्रश्न: बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई 'bob Golden Goal Deposit Scheme' की अवधि कितनी है?

A) 365 Days / 365 दिन

B) 444 Days / 444 दिन

C) 555 Days / 555 दिन

D) 777 Days / 777 दिन

E) 999 Days / 999 दिन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda (BoB) has launched the 'bob Golden Goal Deposit Scheme', a special retail term deposit scheme.

• बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने 'bob Golden Goal Deposit Scheme' नामक विशेष रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है।

• The scheme comes with a tenure of 555 days.

• यह योजना 555 दिनों की अवधि के साथ शुरू की गई है।

• It offers assured returns of up to 7.40% per annum on deposits below ₹3 crore.

• ₹3 करोड़ से कम की जमा राशि पर यह योजना 7.40% प्रतिवर्ष तक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है।

• The scheme is designed for retail customers seeking fixed and attractive returns.

• यह योजना निश्चित एवं आकर्षक रिटर्न चाहने वाले खुदरा ग्राहकों के लिए तैयार की गई है।

• Special interest benefits have been provided for Senior Citizens and Super Senior Citizens.

• वरिष्ठ नागरिकों एवं अति वरिष्ठ नागरिकों को विशेष ब्याज लाभ प्रदान किए गए हैं।

• The deposit scheme aims to encourage long-term savings and financial security.

• इस जमा योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

• Depositors can avail guaranteed returns without exposure to market risks.

• जमाकर्ता बाजार जोखिम के बिना सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

Static GK | स्थैतिक तथ्य

EXAM Genius

• Bank of Baroda Established – 20 July 1908

• बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना – 20 जुलाई 1908

• Headquarters – Vadodara, Gujarat

• मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात

• CEO & MD – Debadatta Chand

• एमडी एवं सीईओ – देबदत्त चंद

• Tagline – India's International Bank

• टैगलाइन – इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक

• Nationalised – 19 July 1969

• राष्ट्रीयकरण – 19 जुलाई 1969
• RBI Established – 1 April 1935
• भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• आरबीआई मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• आरबीआई गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Largest Public Sector Bank – State Bank of India
• सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक – भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

Ques: According to the recent Sensor Tower report, which country emerged as the world's largest market for digital wallet app downloads in 2025?
प्रश्न: हाल ही में जारी सेंसर टॉवर (Sensor Tower) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन-सा देश बना?

A) India / भारत

B) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका

C) China / चीन

D) Brazil / ब्राज़ील

E) Indonesia / इंडोनेशिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• According to a recent Sensor Tower report, India emerged as the world's largest market for digital wallet app downloads in 2025.
• हाल ही में जारी सेंसर टॉवर रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2025 में डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है।
• Sensor Tower data shows that India also ranked first globally in digital wallet

downloads in 2023 and 2024.

• सेंसर टॉवर के आंकड़ों के अनुसार, भारत 2023 और 2024 में भी डिजिटल वॉलेट डाउनलोड के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था।

• Digital wallets collectively crossed 1.8 billion downloads worldwide in Calendar Year (CY) 2025, registering a growth of 3% year-on-year.

• कैलेंडर वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर डिजिटल वॉलेट ऐप्स के 1.8 बिलियन से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3% की वृद्धि दर्शाता है।

• India alone contributed more than 440 million downloads to the global total.

• वैश्विक कुल डाउनलोड में अकेले भारत का योगदान 440 मिलियन से अधिक डाउनलोड रहा।

• The report also revealed that PhonePe became the most downloaded digital wallet application in the world.

• रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि PhonePe दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बन गया।

Key Highlights | मुख्य बिंदु

• Global Digital Wallet Downloads (2025) – Over 1.8 Billion
• वैश्विक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड (2025) – 1.8 बिलियन से अधिक
• India's Contribution – Over 440 Million Downloads
• भारत का योगदान – 440 मिलियन से अधिक डाउनलोड
• Growth Rate – 3% Year-on-Year
• वृद्धि दर – 3% वार्षिक
• Most Downloaded Digital Wallet App – PhonePe
• सबसे अधिक डाउनलोड किया गया डिजिटल वॉलेट ऐप – PhonePe

Ques: The Government of India has extended the validity of the Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0 (CGSMFI-2.0) until which date?

प्रश्न: भारत सरकार ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) की वैधता किस तिथि तक बढ़ा दी है?

A) 31 March 2026

B) 30 June 2026
C) 31 August 2026
D) 31 December 2026
E) 31 March 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India (GoI), through the Ministry of Finance (MoF), has extended the validity of the Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0 (CGSMFI-2.0) until 31 August 2026 or until guarantees worth ₹20,000 crore are issued, whichever is earlier.
• भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (MoF) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस-2.0 (CGSMFI-2.0) की वैधता 31 अगस्त 2026 तक या ₹20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक (जो पहले हो) बढ़ा दी है।
• The government has increased the maximum loan limit for large NBFC-MFIs/MFIs under the scheme from ₹300 crore to ₹1,000 crore.
• सरकार ने इस योजना के तहत बड़े NBFC-MFIs/MFIs के लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दी है।
• The enhanced limit is subject to an overall cap of 20% of their Assets Under Management (AUM).
• यह बढ़ी हुई सीमा उनके Assets Under Management (AUM) के 20% की समग्र सीमा के अधीन होगी।
• The scheme provides credit guarantees to banks and financial institutions for loans extended to microfinance institutions, which further lend to small borrowers.
• यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, जो आगे छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं।
• According to the government release, loans worth ₹770 crore have been sanctioned under the scheme so far.
• सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत ₹770 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

Guarantee Coverage | गारंटी कवरेज

• 80% guarantee cover for Small NBFC-MFIs/MFIs
• छोटे NBFC-MFIs/MFIs के लिए 80% गारंटी कवरेज
• 75% guarantee cover for Medium NBFC-MFIs/MFIs
• मध्यम NBFC-MFIs/MFIs के लिए 75% गारंटी कवरेज
• 70% guarantee cover for Large NBFC-MFIs/MFIs
• बड़े NBFC-MFIs/MFIs के लिए 70% गारंटी कवरेज

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Scheme Name – Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0 (CGSMFI-2.0)
• योजना का नाम – क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस-2.0 (CGSMFI-2.0)
• Nodal Ministry – Ministry of Finance
• नोडल मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
• Launch Date – 20 March 2026
• लॉन्च तिथि – 20 मार्च 2026
• Extended Validity – 31 August 2026 or until ₹20,000 crore guarantees are issued
• विस्तारित वैधता – 31 अगस्त 2026 या ₹20,000 करोड़ की गारंटी जारी होने तक

Ques: Which bank recently launched a new Strategic Business Branch in Mumbai to strengthen its presence in the digital and partnership-led finance sector?
प्रश्न: किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल और साझेदारी-आधारित वित्त क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए मुंबई में एक नई स्ट्रैटेजिक बिजनेस ब्रांच शुरू की है?

A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

C) Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया

D) Canara Bank / केनरा बैंक

E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bank of India (BOI) has unveiled a new Strategic Business Branch in Mumbai to strengthen its presence in the digital and partnership-led finance sector.
• बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने डिजिटल और साझेदारी-आधारित वित्त क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए मुंबई में एक नई स्ट्रैटेजिक बिजनेस ब्रांच शुरू की है।
• The newly launched branch is located at Nariman Point, Mumbai.
• यह नई शाखा नरीमन पॉइंट, मुंबई में स्थित है।
• The branch has been designed to centralise various partnership-driven financing operations.
• इस शाखा को विभिन्न साझेदारी-आधारित वित्तीय गतिविधियों को केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
• It will focus on major financing segments such as Pool Buyout, Co-Lending, Trade Receivables Discounting System (TReDS), and Supply Chain Finance.
• यह शाखा पूल बायआउट (Pool Buyout), को-लेंडिंग (Co-Lending), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) तथा सप्लाई चेन फाइनेंस जैसे प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों पर केंद्रित होगी।
• The initiative is expected to enhance operational efficiency and expand the bank's role in modern digital financing ecosystems.
• इस पहल से बैंक की कार्यकुशलता बढ़ेगी और आधुनिक डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका और मजबूत होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank – Bank of India
• बैंक – बैंक ऑफ इंडिया
• Established – 1906
• स्थापना – 1906
• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई
• MD & CEO – Rajneesh Karnatak
• एमडी एवं सीईओ – रजनीश कर्नाटक
• Tagline – **"Relationships Beyond Banking"**
• टैगलाइन – **"Relationships Beyond Banking"**

Ques : From which date will SEBI's revised trading framework for Exchange Traded Funds (ETFs) come into effect?
प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी Exchange Traded Funds (ETFs) के लिए संशोधित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क किस तिथि से लागू होगा?

A. 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026

B. 15 August 2026 / 15 अगस्त 2026

C. 1 September 2026 / 1 सितंबर 2026

D. 1 October 2026 / 1 अक्टूबर 2026

E. 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• In June 2026, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced a revised trading framework for Exchange Traded Funds (ETFs).
• जून 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Exchange Traded Funds (ETFs) के लिए संशोधित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क जारी किया।
• The new framework introduces dynamic price bands for determining ETF trading limits.
• नए फ्रेमवर्क में ETF के ट्रेडिंग दायरे को निर्धारित करने हेतु डायनेमिक प्राइस बैंड की व्यवस्था की गई है।
• According to SEBI's circular, the revised rules will come into effect from 1 September 2026.

EXAM Genius

• SEBI के परिपत्र के अनुसार, संशोधित नियम 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे।

Key Changes in the Revised ETF Framework | संशोधित ETF फ्रेमवर्क के प्रमुख बदलाव

1. Equity and Debt ETFs

• The existing fixed 20% price band based on Net Asset Value (NAV) has been replaced with a dynamic price band system.
• मौजूदा NAV आधारित 20% स्थिर प्राइस बैंड को डायनेमिक प्राइस बैंड प्रणाली से बदल दिया गया है।
• Initial price band limit will be 10% (excluding overnight and liquid ETFs).
• प्रारंभिक प्राइस बैंड सीमा 10% होगी (ओवरनाइट और लिक्विड ETF को छोड़कर)।
• After a cooling-off period, the limit can be expanded up to 20%.
• कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद इसे 20% तक बढ़ाया जा सकता है।
• If prices hit the upper threshold during trading, the band can be widened further in 5% increments.
• यदि कीमतें ऊपरी सीमा तक पहुंचती हैं, तो प्राइस बैंड को 5% की अतिरिक्त वृद्धि के साथ और विस्तारित किया जा सकेगा।

2. Commodity ETFs (Gold and Silver ETFs)

• Commodity ETFs tracking Gold and Silver will have an initial dynamic price band of ±6%.
• सोना और चांदी आधारित कमोडिटी ETFs के लिए प्रारंभिक डायनेमिक प्राइस बैंड ±6% निर्धारित किया गया है।
• The band can be expanded in stages of 3% after a cooling-off period depending on market movements.
• बाजार की स्थिति के अनुसार कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद इसे 3% के चरणों में बढ़ाया जा सकेगा।

3. Pre-Open Call Auction Mechanism

• SEBI has introduced a Pre-Open Call Auction Mechanism specifically for commodity ETFs.

• SEBI ने विशेष रूप से कमोडिटी ETFs के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन प्रणाली शुरू की है।
• The objective is to improve price discovery and market efficiency.
• इसका उद्देश्य बेहतर प्राइस डिस्कवरी और बाजार दक्षता सुनिश्चित करना है।
• Domestic ETFs will continue to trade only during Indian market hours.
• घरेलू ETFs केवल भारतीय बाजार समय के दौरान ही ट्रेड होते रहेंगे।

Ques : What was India's Wholesale Price Index (WPI)-based inflation rate in May 2026 under the new WPI series (Base Year 2022–23)?
प्रश्न: नई WPI श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) के अनुसार मई 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति दर कितनी रही?

A. 3.88%
B. 8.30%
C. 9.70%
D. 10.20%
E. 11.50%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's **Wholesale Price Index (WPI)-based inflation** increased to **9.7% in May 2026**.
• भारत की **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति** मई 2026 में बढ़कर **9.7%** हो गई।
• The rise in wholesale inflation was mainly driven by higher prices of **crude oil, natural gas, mineral oils**, and to a lesser extent, **manufactured products**.
• थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण **कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों** तथा कुछ हद तक **विनिर्मित उत्पादों** की कीमतों में वृद्धि रही।
• The **Ministry of Commerce and Industry** released a new series of the Wholesale Price Index with an updated **base year of 2022-23**.

• **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की नई श्रृंखला जारी की, जिसका **आधार वर्ष 2022-23** रखा गया है।

• The revised series covers a **wider basket of goods** to better reflect current economic conditions.

• संशोधित श्रृंखला में वस्तुओं का दायरा बढ़ाया गया है ताकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों का बेहतर प्रतिनिधित्व किया जा सके।

• WPI is released by the **Office of the Economic Adviser (OEA)** under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

• WPI को **उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के अंतर्गत **आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA)** द्वारा जारी किया जाता है।

• Previous Month (April 2026) – **8.3%**

• अप्रैल 2026 – **8.3%**

Ques: The Reserve Bank of India's revised directions on advertising, marketing and sale of financial products will come into effect from which date?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री संबंधी संशोधित दिशानिर्देश किस तिथि से प्रभावी होंगे?

A) 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026

B) 1 October 2026 / 1 अक्टूबर 2026

C) 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027

D) 1 April 2027 / 1 अप्रैल 2027

E) 31 December 2026 / 31 दिसंबर 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The **Reserve Bank of India (RBI)** has tightened norms for the advertising, marketing, and sale of financial products.

• **भारतीय रिज़र्व बैंक** (RBI) ने वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित नियमों को और सख्त किया है।

• The revised directions aim to curb **mis-selling** and make regulated entities accountable across all distribution channels.

• संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य **मिस-सेलिंग (गलत तरीके से उत्पाद बेचना)** को रोकना और सभी वितरण चैनलों पर विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

• The norms cover **social media influencers** and **digital marketing intermediaries**, who will be treated as **Direct Selling Agents (DSAs) / Direct Marketing Agents (DMAs)** when engaged for promotion or customer acquisition.

• प्रचार या ग्राहक प्राप्ति के लिए नियुक्त **सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स** और **डिजिटल मार्केटिंग मध्यस्थों** को **डायरेक्ट सेलिंग एजेंट** (DSA) / **डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट** (DMA) माना जाएगा।

• RBI clarified that **third-party incentives to employees of regulated entities (REs)** are prohibited.

• RBI ने स्पष्ट किया है कि **विनियमित संस्थाओं** (REs) **के कर्मचारियों को तीसरे पक्ष द्वारा प्रोत्साहन** (Incentive) **देना प्रतिबंधित** होगा।

• However, **banks and NBFCs** may continue to incentivize their own employees for the sale of financial products.

• हालांकि **बैंक और** NBFCs अपने कर्मचारियों को वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं।

• The directions aim to ensure that incentive structures do not encourage aggressive sales practices or mis-selling.

• इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोत्साहन व्यवस्था आक्रामक बिक्री या मिस-सेलिंग को बढ़ावा न दे।

• The revised directions will become effective from **1 January 2027**.

• ये संशोधित दिशानिर्देश **1 जनवरी 2027** से प्रभावी होंगे।

• Regulated entities may request access to device features such as **camera, location, or similar functionalities**, provided such requests are transparently disclosed to customers.

• विनियमित संस्थाएं **कैमरा, लोकेशन या अन्य डिवाइस सुविधाओं** तक पहुंच का अनुरोध कर सकती हैं, बशर्ते इसकी जानकारी ग्राहक को स्पष्ट रूप से दी गई हो।

• In such cases, it will not be considered a forced action.

• ऐसे मामलों में इसे जबरन कार्रवाई नहीं माना जाएगा।
• Customers can lodge complaints regarding mis-selling within the timeline specified by the concerned regulator.
• ग्राहक संबंधित नियामक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मिस-सेलिंग की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• If no timeline is specified, complaints may be filed within **30 days of receiving the signed agreement**.
• यदि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो ग्राहक **हस्ताक्षरित समझौते की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर** शिकायत कर सकते हैं।
• If mis-selling is proven, the institution must refund the entire amount paid by the customer and compensate for losses according to its approved policy.
• यदि मिस-सेलिंग सिद्ध हो जाती है, तो संस्था को ग्राहक द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करनी होगी तथा स्वीकृत नीति के अनुसार नुकसान की भरपाई करनी होगी।

Customer Consent Provisions | ग्राहक सहमति संबंधी प्रावधान

• RBI has specified various acceptable methods for obtaining customer consent.
• RBI ने ग्राहक की सहमति प्राप्त करने के कई स्वीकार्य तरीके निर्धारित किए हैं।
These include:
• Signed declaration (physical or electronic)
• OTP-based approval
• Digitally recorded confirmation
• Consent embedded in a clearly demarcated section of the agreement
इनमें शामिल हैं:
• हस्ताक्षरित घोषणा (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक)
• OTP आधारित स्वीकृति
• डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की गई पुष्टि
• समझौते के स्पष्ट रूप से चिन्हित भाग में दी गई सहमति

Ques: RBI Reelathon 2026, launched by the Reserve Bank of India (RBI), is primarily aimed at creating awareness about which issue among college students?

EXAM Genius

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू किया गया RBI Reelathon 2026 मुख्य रूप से कॉलेज छात्रों के बीच किस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है?

A) Climate Change and Green Finance / जलवायु परिवर्तन एवं हरित वित्त

B) Financial Inclusion in Rural Areas / ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन

C) Cyber-enabled Financial Frauds / साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी

D) Stock Market Investments / शेयर बाजार निवेश

E) Digital Currency Adoption / डिजिटल मुद्रा अपनाना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI), Thiruvananthapuram, launched RBI Reelathon 2026, an awareness campaign aimed at engaging college students in the fight against cyber-enabled financial frauds.

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), तिरुवनंतपुरम ने RBI Reelathon 2026 नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य कॉलेज छात्रों को साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक करना है।

• The campaign was inaugurated by Ravada A Chandrasekhar, Director General of Police (DGP), at the RBI office in Thiruvananthapuram.

• इस अभियान का उद्घाटन केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवाडा ए. चंद्रशेखर ने RBI कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में किया।

• RBI Reelathon 2026 has been designed as a three-phase state-wide awareness initiative.

• RBI Reelathon 2026 को तीन चरणों वाली राज्यव्यापी जागरूकता पहल के रूप में तैयार किया गया है।

• In the first phase, awareness programmes on smart borrowing and safe digital banking will be conducted across around 150 colleges.

• पहले चरण में लगभग 150 कॉलेजों में स्मार्ट उधारी (Smart Borrowing) और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग (Safe Digital Banking) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

• The second phase includes a reel-making competition for students.
• दूसरे चरण में छात्रों के लिए रील-निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
• Students will create short videos on topics such as illegitimate loan applications, mule accounts, digital financial frauds and cyber hygiene.
• छात्र अवैध ऋण ऐप्स, म्यूल अकाउंट्स, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी तथा साइबर स्वच्छता (Cyber Hygiene) जैसे विषयों पर लघु वीडियो बनाएंगे।
• After multiple rounds of evaluation, shortlisted entries will compete in a Gala Finale scheduled later in 2026.
• कई चरणों के मूल्यांकन के बाद चयनित प्रविष्टियाँ वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
• The top three winners will receive cash prizes of Rs 75,000, Rs 50,000 and Rs 25,000 respectively.
• शीर्ष तीन विजेताओं को क्रमशः 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
• In the third phase, the winning reels will be disseminated through RBI's official social media platforms and the social media channels of Kerala Police, banks, colleges and partner institutions.
• तीसरे चरण में विजेता रीलों को RBI के आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों तथा केरल पुलिस, बैंकों, कॉलेजों और अन्य साझेदार संस्थानों के सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारित किया जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Reserve Bank of India Established – 1 April 1935
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• RBI Headquarters – Mumbai
• RBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Cyber Hygiene – Safe online practices that help users protect themselves from cyber threats and digital frauds.
• साइबर हाइजीन – सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और उपाय, जो उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने में मदद करते हैं।
• Mule Account – A bank account used by fraudsters to transfer or launder

illegally obtained money.
• म्यूल अकाउंट – ऐसा बैंक खाता जिसका उपयोग धोखेबाज अवैध धन के हस्तांतरण या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं।

Ques: The National Stock Exchange (NSE) has decided to allocate what percentage of its annual Corporate Social Responsibility (CSR) corpus to projects listed on the Social Stock Exchange (SSE)?
प्रश्न: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष का कितना प्रतिशत सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है?

A) 2%
B) 5%
C) 12%
D) 10%
E) 20%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The National Stock Exchange (NSE) has decided to allocate 10% of its annual Corporate Social Responsibility (CSR) corpus to projects listed on the Social Stock Exchange (SSE).
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष का 10% सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है।
• The decision follows recent regulatory changes that allow companies to undertake CSR spending through subscription to Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments listed on Social Stock Exchanges.
• यह निर्णय हालिया नियामकीय परिवर्तनों के बाद लिया गया है, जिनके तहत कंपनियां सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध Zero Coupon Zero Principal (ZCZP)

साधनों की सदस्यता लेकर CSR व्यय कर सकती हैं।

• The NSE Social Stock Exchange (SSE) was launched in February 2023.

• NSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) की शुरुआत फरवरी 2023 में की गई थी।

• The SSE facilitates fundraising for social impact projects and non-profit organizations (NPOs).

• SSE सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं तथा गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) के लिए धन जुटाने का मंच प्रदान करता है।

• Under the Companies Act, 2013, eligible companies are required to spend at least 2% of the average net profits earned during the preceding three financial years on CSR activities.

• कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।

• The move is expected to strengthen funding avenues for social enterprises and enhance the impact of CSR initiatives.

• इस पहल से सामाजिक उद्यमों के लिए वित्तपोषण के नए अवसर बढ़ेंगे तथा CSR पहलों के प्रभाव को और मजबूत किया जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• National Stock Exchange of India (NSE) Established – 1992

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना – 1992

• NSE Headquarters – Mumbai

• NSE मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• NSE MD & CEO – Ashish Kumar Chauhan

• NSE के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी – आशीष कुमार चौहान

• Social Stock Exchange (SSE) – A platform that enables social enterprises and non-profit organizations to raise funds through the capital market.

• सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) – एक ऐसा मंच जो सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संगठनों को पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाने की सुविधा प्रदान करता है।

• Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) Instrument – A financial instrument issued by non-profit organizations for raising funds without repayment of principal or interest.

• ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) साधन – गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा धन जुटाने हेतु जारी किया जाने वाला वित्तीय साधन, जिसमें मूलधन या ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं

होता है।

Ques: Which country became the 10th member and first Central Asian country to join the New Development Bank (NDB) in June 2026?
प्रश्न: जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन बना?

A) Kazakhstan / कज़ाखस्तान

B) Kyrgyzstan / किर्गिज़स्तान

C) Tajikistan / ताजिकिस्तान

D) Uzbekistan / उज़्बेकिस्तान

E) Turkmenistan / तुर्कमेनिस्तान

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• In June 2026, the Republic of Uzbekistan became the 10th member and shareholder of the New Development Bank (NDB).
• जून 2026 में उज़्बेकिस्तान गणराज्य न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 10वां सदस्य और शेयरधारक बना।
• Uzbekistan became the first Central Asian country to join the NDB after ratifying the NDB Articles of Agreement (AoA).
• NDB के अनुच्छेद समझौते (Articles of Agreement - AoA) का अनुमोदन करने के बाद उज़्बेकिस्तान NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया।
• Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev signed the law approving the country's accession to the NDB on 21 May 2026.
• उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने 21 मई 2026 को NDB में देश की सदस्यता को मंजूरी देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए।
• The NDB plans to prepare its first projects in Uzbekistan in sectors such as energy, water management, transport, municipal infrastructure, and social

infrastructure.

• NDB उज़्बेकिस्तान में ऊर्जा, जल प्रबंधन, परिवहन, नगर अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों में अपनी पहली परियोजनाएँ शुरू करने की योजना बना रहा है।

• The bank will support these projects through financing in national currencies.

• बैंक इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय मुद्राओं में वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन देगा।

• The mechanism will also utilize national procurement procedures, environmental risk assessment mechanisms, and efficient project preparation and implementation frameworks.

• इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खरीद प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन तंत्र तथा परियोजनाओं की प्रभावी तैयारी एवं कार्यान्वयन व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• New Development Bank (NDB) Established – 2015

• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना – 2015

• NDB Headquarters – Shanghai

• NDB मुख्यालय – शंघाई, चीन

• NDB was established by the BRICS countries to finance infrastructure and sustainable development projects.

• NDB की स्थापना BRICS देशों द्वारा अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु की गई थी।

• Uzbekistan Capital – Tashkent

• उज़्बेकिस्तान की राजधानी – ताशकंद

EXAM Genius